मिलों की मुश्किल: मार्जिन में कमी आ रही है और चीनी के दाम में लगातार आ रही गिरावट के चलते वे कामकाजी पूंजी तक नहीं जुटा पा रहीं

चीनी की MSP तय करने से शुगर इंडस्ट्री में घुलेगी मिठास

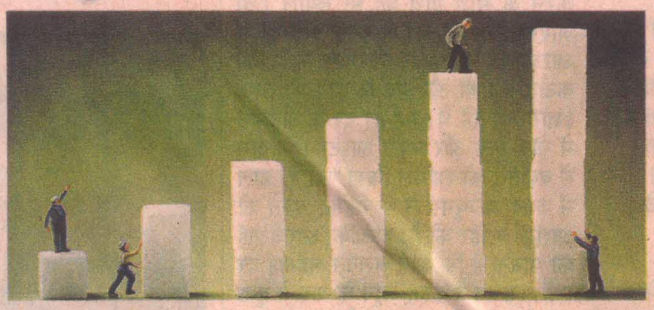

ऑल इंडिया गन्ना उत्पादक संगठन के प्रेसिडेंट

शंकर सिंह वाघेला

"सरकार को कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज (सीएसीपी) के सुझावों के मुताबिक चीनी की वाजिब कीमत का ऐलान करना चाहिए। उसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत यह कदम उठाना चाहिए। इससे गन्ना किसानों के हितों की रक्षा होगी और इंडस्ट्री का लॉस कम करने में मदद मिलेगी"

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली]

गन्ना किसानों ने केंद्र सरकार से चीनी के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) का ऐलान करने की अपील की है। उनका कहना है कि इसी से चीनी मिलों और किसानों की मुश्किल हल होगी। ऑल इंडिया गन्ना उत्पादक संगठन के प्रेसिडेंट शंकर सिंह वाघेला ने कहा, 'सरकार को कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज (सीएसीपी) के सुझावों के मुताबिक चीनी की वाजिब कीमत का ऐलान करना चाहिए। उसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत यह कदम उठाना चाहिए। इससे गन्ना किसानों के हितों की रक्षा होगी और इंडस्ट्री का लॉस कम करने में मदद मिलेगी।'

पिछले कुछ महीनों से चीनी मिलें कह रही हैं कि उनके मार्जिन में कमी आ रही है और वे चीनी के दाम में लगातार आ रही गिरावट के चलते कामकाजी पूंजी तक नहीं जुटा पा रही हैं। मिलों का यह भी कहना है कि प्रॉडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी से भी वे मुसीबत में हैं। चीनी का थोक भाव अभी कई साल के लो लेवल 26 रुपये किलो पर चल रहा है, जबकि प्रॉडक्शन कॉस्ट 34-36 रुपये किलो है। वाघेला ने कहा, 'कुछ लोग यह सवाल उठा सकते हैं कि एमएसपी तो सरकार का कंट्रोल्ड प्राइस है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि चीनी मिलों को एमएसपी से अधिक भाव पर चीनी बेचने की इजाजत है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे उस पर भी बोझ नहीं आएगा और इंडस्ट्री के पास गन्ना किसानों को देने के लिए पैसा आएगा।'

- **सरकार ने** शुगर इंडस्ट्री को राहत देने के लिए शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी
- **साथ ही** एथेनॉल की कीमत भी बढ़ाई गई, जिसकी खरीदारी ऑयल कंपनियां चीनी मिलों से करती हैं
- **केंद्र ने** एडवांस अथॉराइजेशन स्कीम के तहत इंपोर्ट की जाने वाली चीनी को एक्सपोर्ट करने की मियाद भी 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी थी

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हालिया शुगर प्रॉडक्शन एस्टिमेट में कहा था कि इस सीजन में 2.8 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हो सकता है। वहीं, पिछले सीजन की भी 1 करोड़ टन से अधिक चीनी बची हुई है। इसका मतलब यह है कि 1 अक्टूबर से जब नया शुगर सीजन शुरू होगा, तब स्टॉक 3.8 करोड़ टन का होगा। भारत में 2.5 करोड़ टन चीनी की खपत का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि अगले सीजन में चीनी की सप्लाई मांग से काफी अधिक रह सकती है। 2014-15 शुगर सीजन में 30 जून तक 2.82 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था। अक्टूबर से पहले तक के बचे हुए समय में और 2.5 लाख टन चीनी का प्रॉडक्शन हो सकता है। शुगर इंडस्ट्री की दिक्कतों का असर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर भी पड़ रहा है। किसानों को मिलों से इस सीजन में 18,000 करोड़ रुपये लेने हैं, जबकि पिछले सीजन में यह रकम 10,000 करोड़ थी।

सरकार ने इंडस्ट्री को राहत देने के लिए शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। इसके साथ एथेनॉल की कीमत भी बढ़ाई गई, जिसकी खरीदारी ऑयल कंपनियां चीनी मिलों से करती हैं। केंद्र ने एडवांस अथॉराइजेशन स्कीम के तहत इंपोर्ट की जाने वाली चीनी को एक्सपोर्ट करने की मियाद भी 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी थी। सरकार ने मिलों के लिए रियायती दरों पर 60 अरब रुपये के लोन का भी ऐलान किया था, जिससे वे किसानों की बकाया रकम चुका सकें।

The economic Times.
5-8-15